LOSSES DUE TO RIVER GANGA IN BUXAR AND BHOJPUR AREA OF NORTH BIHAR

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार): उपासभाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान बिहार के बक्सर और भोजपुर जिलों में गंगा की धारा से हो रहे कटाव के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं

महोदय, बक्सर में पुरातात्विक महत्व का एक ऐतिहासिक किला है जिस की भूमि का गंगा की धारा से निरन्तर कटाव हो रहा है। महोदय, उस किले का कटाव होने के बाद बक्सर पूरा गंगा के अंदर चला जाएगा। इसी तरह बक्सर से कोइलवार तक का क्षेत्र जिस के अंदर बक्सर और भोजपुर जिले के 7 प्रखंड आते हैं, इन सातों प्रखंडों के गंगा के किनारे के गांवों की भूमि का और कृषि भूमि का कटाव हो रहा है। महोदय, इस से राज्य सरकार और केन्द्र सरकार भी अवगत है। यहां का एक गांव ठगनी का डेरा पांच साल पूर्व पूरे तौर पर गंगा समाहित हो गया था। इस तरह से सैकड़ों एकड़ भूमि का कटाव हो रहा है जिस कारण गांवों के उजड़ने की स्थिति है और काफी पैदावार वाली कृषि भी गंगा की धारा में चली जा रही है। महोदय, वहां की स्थिति इतनी भयावह है कि पिछले लोक सभा इलेक्शन में कई गांवों ने चुनावों का बहिष्कार किया था।

सर, इस समस्या को लेकर कई वर्षो से आंदोलन हो रहे हैं। इस समस्या से निपटने और कटाव से वहां की भूमि को संरक्षित करने पर काफी पैसा लगेगा। महोदय, मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार को यह मामला अपने ध्यान में लेना चाहिए और इस समस्या के समाधान के लिए एक मनसुखी योजना तैयार करनी चाहिए ताकि वहां के भूमि कटाव को रोका जा सके। सर, यह कटाव क्षेत्र करीब 60 किलोमीटर लंबी पट्टी पर है।

उपसभाध्यक्ष जी, यह भी ध्यान में लाना चाहते हैं कि पूर्व में जब बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध का निर्माण हुआ उस वक्त भी गंगा से इस कटाव की समस्या ध्यान में थी और इसके लिए बक्सर जिले के अंतर्गत ब्रहपुर प्रखंड में 50 लाख ईंट एक साइड पर डाली गई थीं और हजारों ट्रक स्टोन चिप्स वहां लाकर रखी गई, जो दस वर्ष, पन्द्रह वर्ष से वहां पडी रहीं। आज उन पचास लाख ईंट में से एक लाख ईंट मुश्किल से बची हैं, बाकी लोग उठाकर अपने-अपने घर ले गए या दूसरे काम में वह लग गई और इसी तरह निरंतर स्टोन चिप्स की भी चोरी होती रही । इसमें केन्द्र सरकार का भी पैसा लगा था। मेरा कहना यह है कि वर्षो से इस समस्या को नजर अंदाज किया जा रहा है और अब स्थिति यह है कि खतरा दिनों-दिन बढ़ रहा है।

सभापति जी, मैंने पूर्व में ही कहा कि पिछले इलेक्शन के दौरान लोग चुनाव के बहिष्कार पर उतर आए थे। वह आगे बहिष्कार करें या न करें, में उस पर जोर नहीं देना चाहता , लेकिन वास्तविकता यह है कि यह समस्या काफी गंभीर है। केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, राज्य

सरकार से इस पर योजना मांगे और नहीं तो अपनी तरफ से इसके लिए एक स्टडी टीम भेजे और एक मनसुखी योजना तैयार करे ताकि उपजाऊ कृषि भूमि को और इस इलाके में होने वाले सैकड़ो कटाव से बचाया जा सके। यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री अधिक शिरोडकर): श्री नरेश यादव। नहीं हैं। श्री संजय निरुपम

NEED TO PROVIDE APPROPRIATE SECURITY TO V.I.PS. IN MAHARASHTRA

श्री संजय निरूपम(महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक बेहद गंभीर प्रश्न की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्था है। यहां तरह-तरह के दल हैं। एक दल दूसरे दल के खिलाफ चुनाव लड़ता है और उस चुनाव में हम एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते हैं, भाषण देते हैं। चुनाव के बाद जब रिजल्ट आता है तो किसी दल को सत्ता मिलती है और कोई दल विपक्ष में बैठता है। सत्ता में आने के बाद एक परंपरा है कि विपक्ष में जो नेता महत्वपूर्ण होते हैं, सुरक्षा की दृस्टि से जो संवेदनशील होते हैं, उनकी सुरक्षा के मामलों में कम से कम खिलवाड़ नहीं किया जाता है। इसका ताजा उदाहरण है कि हमारी केन्द्रीय सरकार ने अभी कांग्रेस की अध्यक्षा माननीया श्रीमती सोनिया गांधी की जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको लगभग दस वर्षो के लिए फिर से बढ़ाया है । यह एक अच्छी बात है और इस तरह की परंपरा का पालन होना चाहिए, मगर दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र में बिल्कुल इसके विपरीत हो रहा है। महाराष्ट्र में इस समय दो कांग्रेस की एक संयुक्त सरकार है, जो एक डेढ़ महीना पहले सत्ता में आई है। जबसे वह सरकार सता में आई है तब से महाराष्ट्र के जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं, वीआईपीज़ हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो संवेदनशील लोग हैं उनकी सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। महाराष्ट्र के गृहमंत्री लगातार बयान दे रहे हैं कि इन वीआईपीज़ की सुरक्षा व्यवस्था को रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू करने के पीछले राजनैतिक तौर पर एक भेदभाव की भावना दिख रही है।

उपसभाध्यक्ष जी, विशेषकर के मैं हमारे नेता माननीय शिव सेना प्रमुख माननीय श्री बाला साहब ठाकरे जी की सुरक्षा व्यवस्था की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के नाम पर वहां के गृहमंत्री लगभग रोज तरह-तरह के कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं कि उनकी सुरक्षा कम की जाएगी, उनकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इस तरह की बातें आ रही हैं। कल परसों मुंबई के एक अखबार में बयान आया है, एक न्यूज आई है, उस न्यूज का हैडिंग है